क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 287, गुरुवार, 15 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी गिरफ्तार

एजेंसी, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले से सुरक्षा बलों ने बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किये हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि भरोसेमंद सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने अवंतिपुरा क्षेत्र के पंजगाम में एक नाके से उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा, ' 'सुरक्षा बलों ने जांच के दौरान यूबीजीएल, ग्रेनेड और गोलियां और दोष सिद्ध करने वाली अन्य सामग्री सहित उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान जैन मोहम्मद शेख और नासिर-उल-इस्लाम के तौर पर हुई और दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन से संबद्ध हैं। कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

11 दिसंबर से 8 जनवरी तक हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, CCPA ने की सिफारिश

नई दिल्ली। मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति (सीसीपीए) ने संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से आठ जनवरी तक चलाने की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली सीसीपीए की बैठक मंगलवार रात उनके आवास पर हुई और सत्र की तारीख पर विचार-विमर्श हुआ। सूत्रों ने बताया कि सीसीपीए ने 11 दिसंबर से आठ जनवरी तक शीतकालीन सत्र आहूत करने की सिफारिश की है। संसद का शीतकालीन सत्र अमूमन नवंबर में शुरू होता है। हालांकि, यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सत्र दिसंबर में शुरू होगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण इस साल सत्र में देरी हुई है। पिछले साल भी यह दिसंबर में शुरू हुआ था। इसके पीछे की वजह गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, संभावना है कि इस बार शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल राफेल सौदा, किसानों के प्रदर्शन, कीमतों में बढ़ोतरी आदि जैसे अहम मुद्दों को उठा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की 17 दिनों की बैठक में कुल 112 घंटे तक कार्यवाही चली थी। इसमें कुल 21 विधेयक पारित किए गए थे। यह सन् 2000 के बाद इस मानसून सत्र में सबसे ज्यादा कार्यवाही थी। इस सत्र में तेदेपा सदस्य श्रीनिवास केसिनेनीर की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 20 जुलाई को 11 घंटे 46 मिनट की चर्चा चली थी।

इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-29 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

श्रीहरिकोटा, एजेंसी। देश के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट-29 के साथ जीएसएलवी एमके 3-डी 2 रॉकेट को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। जीसैट-29 उपग्रह उच्च क्षमता वाले का और कू-बैंड के ट्रांसपोंडरों से लैस है। इससे पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर सहित देश के दूर-दराज के इलाकों में संचार जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने कहा कि इसका क्रेडिट इसरो की पूरी टीम को जाना चाहिए।

रिश्वतखोरी मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को मिली जमानत

नई दिल्ली, एजेंसी। बेल्लारी के खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को 18 करोड़ रुपये की रिश्वतरोखी केस में जमानत मिल गई है। रेड्डी को रविवार को बेंगलुरू में गिरफ्तार किया गया था। पोंजी स्कीम चलाने वाले एक शख्स के साथ संभावित संबंध को लेकर रेड्डी के खिलाफ जांच की जा रही है।

पुष्कर (राजस्थान) में ऊंट मेले के लिए मंगलवार को अपने ऊंटों को ले जाता चरवाहा।

»» सबरीमाला प्रवेश फैसले पर रोक से किया इनकार

पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई 22 जनवरी को

नई याचिकाओं पर सुनवाई पुनर्विचार याचिकाओं के निपटारे के बाद

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया परंतु वह इस पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर खुले न्यायालय में 22 जनवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चैंबर में इन पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर किया और सारे मामले में न्यायालय में सुनवाई करने का निश्चय किया। चैंबर में होने वाली कार्यवाही में वकील उपस्थित नहीं रहते हैं। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश् में कहा, सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सभी लंबित आवेदनों के साथ 22 जनवरी, 2019 को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। हम स्पष्ट करते है कि इस न्यायालय के 28 सितंबर, 2018 के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं है। इससे पहले, दिन में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के निर्णय पर पुनिर्वचार के लिये दायर याचिकाओं का निबटारा होने के बाद ही इस मुद्दे पर किसी नई याचिका की सुनवाई की जाएगी। सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के शीर्ष अदालत के 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिये 48 याचिकाएं दायर की गयी हैं।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने नौ अक्टूबर को नेशनल अय्यप्पा अनुयायी एसोसिएशन की पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

सरकार ने नहीं बताई राफेल की कीमत, कहा-विरोधी उठा सकते हैं फायदा, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के लिये फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे की कोर्ट की निगरानी में जांच के लिये दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश बाद में सुनायेगा। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 36 राफेल लड़ाकू विमानों के दाम के संबंध में जानकारी सार्वजनिक करने से इंकार किया और कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक होने का ' 'हमारे विरोधी लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में राफेल सौदे के दामों की जानकारी सीलबंद लिफाफे में सौंपने के दो दिन बाद केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के सामने राफेल विमानों के दाम से संबंधी गोपनीयता उपबंध का बचाव किया।

संसद को कभी राफेल की कीमत के बारे में नहीं बताया गया: अटार्नी जनरल

सरकार की इस दलील पर, पीठ ने कहा कि राफेल विमानों के दाम पर चर्चा केवल तभी हो सकती है जब इस सौदे के तथ्य जनता के सामने आने दिये जायें। पीठ ने कहा, ' 'हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या कीमतों के तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं। पीठ ने कहा कि तथ्यों को सार्वजनिक किये बगैर इसकी कीमतों पर किसी भी तरह की बहस का सवाल नहीं है। अटार्नी जनरल वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि इन विषयों पर विशेषज्ञों को गौर करना है और ' 'हम कह रहे हैं कि संसद को भी विमानों के पूरे दाम के बारे में नहीं बताया गया है। वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि न्यायालय न्यायिक रूप से यह फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है कि कौन सा विमान और कौन से हथियार खरीदने जाएं क्योंकि यह विशेषज्ञों का काम है। एक याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि इस सौदे के लिए फ्रांस ने कोई सरकारी गारंटी नहीं दी है, इस आरोप पर अटार्नी जनरल ने स्वीकार किया कि कोई सरकारी गारंटी नहीं दी गई है लेकिन कहा कि फ्रांस ने सहूलियत पत्र दिया है जो सरकारी गारंटी की तरह ही है।

राफेल की कीमतों की जानकारी दी गई तो विरोधी उठा सकते है लाभ: सरकार

वेणुगोपाल ने कहा कि (संप्रग सरकार के दौरान के) पिछले अनुबंध में विमान जरूरी हथियार प्रणाली से लैस नहीं थे और सरकार की आपत्ति इस तथ्य को लेकर ही है कि वह अंतर-सरकार समझौता और गोपनीयता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने राफेल विमानों, इस पर लगने वाले हथियारों तथा अन्य जरूरतों की पूरी जानकारी पहले ही सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंप दी हैं। राफेल विमानों के दाम से जुड़े गोपनीयता उपबंध का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, ' 'अगर दाम की पूरी जानकारी दे दी गई तो हमारे विरोधी इसका लाभ उठा सकते हैं। दाम के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने से इंकार करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि वह दाम के मुद्दे पर न्यायालय की इससे आगे कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि पहले इन विमानों को जरूरी हथियार प्रणाली से लैस नहीं किया जाना था और सरकार की आपत्ति इस तथ्य को लेकर ही है कि वह अंतर-सरकार समझौता और गोपनीयता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करना चाहती। सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि नवंबर, 2016 की विनिमय दर के आधार पर सिर्फ लड़ाकू विमान की कीमत 670 करोड़ थी। भारत ने अपनी वायु सेना को सुसज्जित करने की प्रक्रिया में उड़ान भरने के लिये तैयार अवस्था वाले 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदने का समझौता किया था। इस सौदे की अनुमानित लागत 58,000 करोड़ रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना के अधिकारियों की दलील सुनें

पीठ ने कहा कि वह वायु सेना की जरूरतों से संबंधित मसले पर सुनवाई कर रही है और वह इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के किसी अधिकारी की जगह वायु सेना के अधिकारी को सुनना चाहती है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ' 'हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या कीमतों के तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं। पीठ ने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि तथ्यों को सार्वजनिक किये बगैर इसकी कीमतों पर किसी भी तरह की बहस का सवाल नहीं है। पीठ ने कहा, ' 'हम वायु सेना की जरूरतों पर विचार कर रहे हैं और हम राफेल विमान के बारे में वायु सेना के किसी अधिकारी से जानना चाहेंगे। हम इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारी को नहीं बल्कि वायु सेना के अधिकारी को सुनना चाहते हैं। इस मामले में भोजनावकाश के बाद बहस शुरू होने पर वायुसेना के उपप्रमुख एअर मार्शल वी आर चौधरी और दो अन्य अधिकारी न्यायालय की मदद के लिये पीठ के समक्ष पेश हुये।

अटार्नी जनरल बोले मैंने खुद राफेल की कीमत की जानकारी नहीं है

अटार्नी जनरल ने बहस के दौरान राफेल विमानों की कीमतों से संबंधित गोपनीयता के प्रावधान का बचाव किया और कहा, ' 'यदि कीमतों के बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी गयी तो हमारे शत्रु इसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर, 2016 की विनिमय दर के आधार पर सिर्फ लड़ाकू विमान की कीमत 670 करोड़ थी।

प्रशांत भूषण को कहा, हम आपको पूरी तरह से सुन रहे हैं

भूषण ने जब गोपनीयता के प्रावधान का मुद्दा उठाया तो वेणुगोपाल ने कहा, ' 'गोपनीय समझौता गोपनीय ही रखना होगा और अब वह न्यायालय में इसे पेश कर रहे हैं। भूषण, जो अपनी और भाजपा के दो नेताओं पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी की ओर से पेश हुये, ने आरोप लगाया कि सरकार गोपनीयता के प्रावधान की आड़ लेकर राफेल विमानों की कीमतों का खुलासा नहीं कर रही है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने भूषण से कहा, ' 'हम आपको पूरी तरह सुन रहे हैं। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी न्यायालय को दी थी सुनवाई के दौरान भूषण ने कहा कि एक विमान की कीमत 155 मिलियन यूरो थी।

अधिकारियों की लोकेशन ट्रैक हो रही मोबाइल फोन पर

अधिकारियों के वाहनों पर लगे जीपीएस

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों के वाहनों पर जीपीएस लगा दिया गया है। गाड़ी में जीपीएस लगते ही अधिकारियों के कार्यालय में होने पर उनकी गाड़ी की लोकेशन मोबाइल पर सचिवालय के पास दिख जाता है। अगर अधिकारी किसी कार्यवश अन्यत्र गए हैं तो गाड़ी की लोकेशन मोबाइल पर उपलब्ध रहती है। गाड़ी के साथ अधिकारी का लोकेशन भी ट्रैक हो पा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधान सभा अध्यक्ष, विधान सभा के अधिकारी, जिला जज, मुख्य चुनाव अधिकारी व लोकायुक्त की गाड़ी को जीपीएस लगाने से छूट दी गई है। विजिलेंस निदेशालय, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, ह्यूमन राइट कमेटी, एनसीसी व दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने भी इसी तर्ज पर जीपीएस लगाने से छूट की मांग की थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने कहा कि जिन सरकारी वाहनों में जीपीएस नहीं लगाए जाएंगे,उसमें ईधन नहीं दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अगर एक नौकरशाह के पास एक से ज्यादा विभाग हैं तो वे एक ही गाड़ी रखने के हकदार होंगे। यानि दो या तीन विभाग के सचिव का प्रभार रहने पर नौकरशाह के पास सभी विभाग की एक गाड़ी उपलब्ध रहती थी। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

सचिव या प्रधान सचिव के पास एक गाड़ी ही रहेगी।

यानि जितने विभाग उतने वाहन की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों के पास भी कई विभागों की गाड़ियां रहती थी। अब यह संभव नहीं हो सकेगा। जीपीएस के द्वारा प्रत्येक गाड़ी की वर्तमान लोकेशन जानी जा सकती है इसलिए सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग के ऑडिट में पता चला है कि अधिकारी और ड्राइवर वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लॉगबुक नहीं भर रहे हैं। विभाग को जानकारी नहीं मिल पा रही कि इन वाहनों को किस उद्देश्य से और कहां चलाया जा रहा है।

वाहन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से कहां से कहां तक के लिए किया गया यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सभी गाड़ियों में जीपीएस लगने से पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो गई है।

अवतार सिंह भड़ाना ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ठोकी ताल, बोले-सीट अभी तय नहीं

मेरठ, एजेंसी। मीरापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और चार बार लोकसभा के सांसद रह चुके अवतार सिंह भड़ाना ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताल ठोंक दी है। अवतार सिंह भड़ाना ने दावा किया है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह सीट कौन सी होगी, इसके बारे में अभी तय नहीं है। उनका कहना है कि जिस भी सीट से पार्टी हाईकमान कहेगा उसी सीट से चुनाव लड़ लूंगा। अवतार सिंह भड़ाना तीन बार हरियाणा में फरीदाबाद से और एक बार मेरठ से सांसद रह चुके हैं। चार बार सांसद रहने के बाद अब वह मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। इस बार फिर से वह लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं और स्वंय भी दावा कर रहे हैं कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वह कौन सी लोकसभा सीट से 2019 के सियासी रण में उतरेंगे, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट अभी तय नहीं है, लेकिन यह तय है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

धर्मसभा में शामिल होने के लिए एक लाख लोग पहुंचेंगे अयोध्या

अवतार सिंह भड़ाना का सियासी सफर

1988- हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने अवतार भड़ाना को बिना विधायक बने ही छह माह के लिए शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री बनाया था।

-1991- अवतार भड़ाना कांग्रेस की टिकट पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने

-1996- अवतार भड़ाना कांग्रेस की टिकट पर फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के रामचंद्र बैंदा से चुनाव हार गए।

-1998- मध्यावधि लोकसभा चुनाव में अवतार भड़ाना को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला और वे जनता दल की

टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, इस चुनाव में भी भाजपा के रामचंद्र बैंदा जीते।

- 1999- लोकसभा चुनाव में अवतार भड़ाना को कांग्रेस ने मेरठ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा और भड़ाना यहां पर चुनाव जीत गए।

- 2004- लोकसभा चुनाव में अवतार भड़ाना फिर से फरीदाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए।

-2009- अवतार भड़ाना फरीदाबाद से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते

2014- अवतार भड़ाना कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर से 4.67 लाख वोट से चुनाव हार गए

2014- हरियाणा विधानसभा चुनाव में अवतार भड़ाना इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए और उन्होंने इनेलो के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम किया।

2015- दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवतार भड़ाना इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी ने इन्हें दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा। अवतार भड़ाना को भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अवतार भड़ाना मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए।

संपादकीय

संकल्प एवं दृढ़ इच्छाशक्ति

वाराणसी तक मालवाहक जहाज का चलना निस्संदेह ऐतिहासिक घटना है। देश के संकल्प एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में जल यातायात को पुनर्जन्म देने की घोषणा की तो उपहास तक उड़ाया गया। जब काम आरंभ हुआ तो अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी की गई..पर्यावरण से लेकर अनेक कानूनी अड़चनें लाई गई। गंगा की पेटी में कई जगह पानी भी इतना नहीं था कि जहाज को निर्बाध चलाया जाए। कई बार कई जगह परीक्षण जहाज फंस गया। आज कहा जा सकता है कि अगर आपके अंदर निश्चय हो और उस पर आलोचनाओं और विरोधों की अनदेखी करके काम करते रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। भारत अंग्रेजों के आने तक जल यातायात प्राथमिकता वाला देश था। भारत की व्यापारिक-सांस्कृतिक-आर्थिक शक्ति का यह मुख्य आधार था। देश में आज भी जितनी निदयां हैं, उनका योजनापूर्वक उपयोग हो तो फिर से उसी स्थिति को पाया जा सकता है। जल यातायात सबसे कम खर्चीला और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। जल यातायात जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा सड़कों से मालवाहन का वजन घटेगा। भारत की नदियों का जुड़ाव बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से है। उन देशों से फिर दूसरे देशों का जल स्रोत जुड़ा है। नदियां समुद्र से मिलती हैं। इस तरह जल यातायात को प्राथमिकता दी जाएतो कई देशों से सीधे आवागमन हो जाएगा। हल्दिया से वाराणसी मालवाहक जहाज का आना भविष्य का आधार बन सकता है। गंगा में शुरु आत से कई अनुभव आए हैं। कहीं-कहीं नदी की पेटी में खुदाई करनी पड़ी। वाराणसी से अब आगे का कम चल रहा है। इसके बाद एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी जलयान का उपयोग किया जाएगा। आगामी कुंभ में वाराणसी से प्रयाग तक एक घंटे में जहाज से लोग पहुंचेंगे। वास्तव में इसका एक लाभ यही है कि अधिक दूरी का सफर काफी कम खर्च में पूरी सुरक्षा से पूरी की जा सकती है। जाहिर है, इस सफल प्रयोग का तेजी से विस्तार करने की आवश्यकता है। राज्यों की सरकारें भी केंद्र से तकनीकी और वित्तीय मदद लेकर जल यातायात की ओर अग्रसर हों इसके लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। कल्पना करिए, यह हो गया तो सड़कों और रेल मार्ग का वजन कितना कम होगा। तेल की खपत में कितनी कमी आएगी। देश की कामना है कि हम फिर से दुनिया में जल यातायात का सिरमौर बनें।

नक्सलियों की धमकी

18 विधानसभा सीटों पर जिस निर्भिकता के साथ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वह न केवल काबिलेतारीफ है वरन इसे सालों तक याद किया जाएगा। वोट देने वालों के हाथ जिस्म से अलग कर दिए जाएंगे, नक्सलियों की इस धमकी का छत्तीसगढ़ की जनता ने करारा जवाब दिया। जनता ने बेपरवाह होकर वोट डाले। यहां फीसद 70 से ज्यादा मतदान की खबर है। खासकर नक्सल प्रभावित सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिलों के कई मतदान केंद्रों पर जहां पिछले चुनाव में शून्य मतदान हुआ था, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यह सुरक्षाबलों और सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगा। लेकिन इसका सबसे ज्यादा श्रेय उन मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने नक्सलियों की धमकी को ठेंगा दिखा दिया। वाकई पहले चरण में बैलेट ने बुलेट को परास्त कर दिया। गौरतलब है कि चुनाव से पहले ही नक्सलियों ने जनता को इससे दूर रहने के लिए भय का वातावरण बना रखा था। लगातार सुरक्षाबलों पर हमला करना इसी रणनीति का हिस्सा था। यहां तक कि चुनाव के दिन भी सुरक्षाबलों को निशाना बनाया गया और आइईडी ब्लास्ट भी किया गया। मगर लोकतंत्र की विजय श्री में जनता के बुलंद हौसले ने इसे और मजबूती दी। हालांकि पिछले सभी चुनावों से तुलना करें तो इस बार मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा लेकिन यह सराहनीय इसलिए रहा क्योंकि नक्सलियों में ज्यादा आक्रामकता थी। मगर इस बार समाज की मुख्यधारा से कटे नक्सलियों की एक न चली। गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी जनता के हौसले को परास्त नहीं कर सकी। अब अगले चरण का चुनाव 20 नवम्बर को होना है। स्वाभाविक है कि जनता के इस जवाब के संदेश को नक्सली संजीदगी से लें और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए समाज की मुख्यधारा में वापस लौटें। आदिवासी जनता की आवाज बनने का दंभ भरने वाले नक्सली उन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण और दोहन करते रहे हैं। इस बात को अब हर कोई समझ चुका है। सो नक्सली अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं। जबकि लोकतंत्र को मजबूती देने में चुनाव प्रक्रिया और जनता का मताधिकार पहली सीढ़ी है। इसे किसी भी तरीके से कमजोर नहीं किया जा सकता है। जब भी लोकतंत्र के शत्रुओं ने ऐसी हिमाकत की है, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है।

बच्चों की स्थिति दयनीय

दुनिया के बाल मजदूरों में भारत की लगभग 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को बच्चों से बहुत ही लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। यहां तक कि उन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रुचि भी बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही है। फिर भी देश में बच्चों की स्थिति दयनीय है। बाल श्रम की बात हो, बाल व्यापार, बाल यौन शोषण या बाल अधिकार की बात हो उन्हें जरूरत मुताबिक संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिल पा रहे। इस विषय पर नीति निर्धारकों को भी सोचने की जरूरत है कि बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण, मनोरंजन, खेल पर कुल मिलाकर बच्चों के लिए सरकार कितना ''बजट' निर्धारित करती है। एक तरफयह स्थिति है तो दूसरी तरफ`बचपन' छिनता जा रहा है। आज वैश्वीकरण के युग में समाज स्वयं अपने बच्चों का बचपन छीन रहा है।

सतीश पेडणोकर

पूरे देश में बाल दिवस फिर मनाया जाएगा। बहुत सारे आयोजन होंगे। हर आयोजन में बच्चों के अधिकारों एवं सुरक्षा की र्चचा के साथ-साथ उन्हें भारत के भविष्य के रूप में दशर्या जाएगा लेकिन कड़वा सच है कि दुनिया में पहला देश भारत ही है जहां सर्वाधिक बाल श्रम होता है। दुनिया के बाल मजदूरों में भारत की लगभग 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को बच्चों से बहुत ही लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। यहां तक कि उन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रुचि भी बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही है। फिर भी देश में बच्चों की स्थिति दयनीय है। बाल श्रम की बात हो, बाल व्यापार, बाल यौन शोषण या बाल अधिकार की बात हो उन्हें जरूरत मुताबिक संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिल पा रहे। इस विषय पर नीति निर्धारकों को भी सोचने की जरूरत है कि बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण, मनोरंजन, खेल पर कुल मिलाकर बच्चों के लिए सरकार कितना ''बजट' निर्धारित करती है। एक तरफ यह स्थिति है तो दूसरी तरफ''बचपन' छिनता जा रहा है।

आज वैश्वीकरण के युग में समाज स्वयं अपने बच्चों का बचपन छीन रहा है। बच्चों से आधिकाधिक अपेक्षाएं, उनकी रुचि के अनुसार हम तैयार नहीं। अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को तैयार करने की सोच लिए हुए हैं। इसी बोझ से आज का ''बचपन' दबता जा रहा है। देश में बच्चों की संख्या 41.4 करोड़ से अधिक है, जो दुनिया के अन्य किसी भी देश में बच्चों की संख्या की तुलना में सर्वाधिक है। दु:खद है कि अनेक बच्चे सामाजिक-आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारणों से अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं। वे भेदभाव, उपेक्षा और शोषण के सहज शिकार हो जाते हैं। इनमें से बहुत से बच्चों के परिवार दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके लिए आजीविका के साधन बहुत सीमित हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अन्य काम की तलाश में घर-बार छोड़कर शहरों और नगरों में पलायन कर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चे ऐसे माहौल से वंचित हो जाते हैं, जिसमें सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए अपना समुचित विकास कर सकें। वास्तव में यह दुभाग्यपूर्ण स्थिति है जिससे निपटने के लिए सभी संबद्ध लोगों को मिल कर प्रयास करने की आवश्यकता हैं।

भारत के संविधान में बच्चों तथा उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। हमने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते का अनुमोदन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चों को सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने के लिए ऐसा सुरक्षित और ममता-भरा माहौल मिले जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुनिश्चित हो कि सभी बच्चे स्कूल जाएं, उनका शोषण करने वालों को सजा देने के उपयुक्त कानून बनें, बच्चों के सामने मौजूद खतरों के बारे में समाज को जानकारी हो तथा सरकार, निर्वाचित जन-प्रतिनिधि और समाज बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर कारगर ढंग से ध्यान दें ताकि उनकी बेबसी को कम किया जा सके। बाल संरक्षण शब्द का उपयोग विभिन्न संगठन विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूपों में करते हैं। इस शब्द का अर्थ होगा हिंसा, दुरुपयोग और शोषण से संरक्षण। सीधे शब्दों में कहें तो बाल संरक्षण का अर्थ प्रत्येक बच्चे के इस अधिकार को संरक्षण देना है कि उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए। इससे अन्य अधिकरों को भी बल मिलता है अर्थात सुनिश्चित होता है कि बच्चों को वह सब कुछ प्राप्त हो जिसकी उन्हें जीवित रहने, विकसित होने और फ लने-फूलने के लिए आवश्यकता है। 2002 में बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में राष्ट्रों ने अधिवेशन में अनुमोदित ''अ वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रेन' (बच्चों के लायक दुनिया) घोषणा को साकार करने का संकल्प व्यक्त किया। यह संकल्प ऐसी दुनिया के निर्माण का है जिसमें ''सभी लड़कियां और लड़के अपने बचपन का आनंद ले सकें..जिसमें उन्हें भरपूर प्यार, सम्मान और दुलार मिले..जिसमें उनकी सुरक्षा और खुशहाली सबसे पहले हों और जिसमें वे स्वास्थ्य, शांत और गरिमा के साथ बड़े हों।

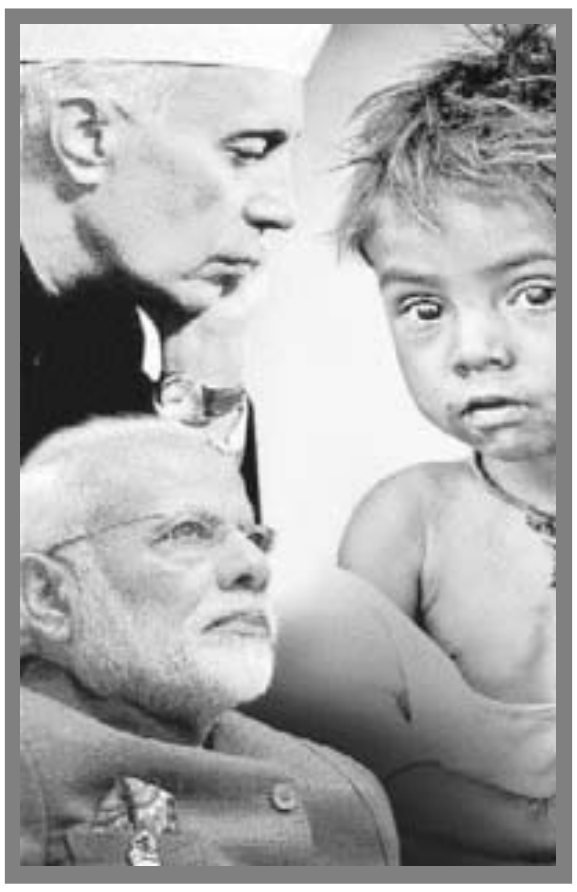

' ये भावनाएं कानूनी मानदंडों से परे हैं। विश्व की हर संस्कृति में बच्चे सबके दुलारे होते हैं। फिर भी हम उनके संरक्षण में विफल रहते हैं। देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और सुरक्षा के लिए राष्ट्र बालक अधिकार संरक्षण आयोग मार्च, 2007 में बाल अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के किशोर की परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा 2(ब) के अनुरूप बाल अधिकारों में संयुक्त राष्ट्र संघ संधि के तहत अधिकार सम्मिलित हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) कानून, 2000 क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन में बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। इस कनवेंशन में न्यायिक कार्यवाहियों का सहारा लिए बिना समय-सीमा तक पीड़ित बालकों के सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए बल दिया गया है। भारत सरकार ने ग्यारह दिसम्बर,1992 को इस कनवेंशन के निर्णयों को स्वीकार किया और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख तथा संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख एवं संरक्षण एवं उपचार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संबंधित न्याय निर्णयन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा उनके अंतिम पुर्नवास के लिए इस अधिनियम को तीस दिसम्बर, 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य आधार बालकों के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए उनके हित में देखरेख, संरक्षण व पुर्नवासन का लाभ किया जाना है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि जब तक समन्वित तरीके से हम सभी सरकार, गैर-सरकारी संगठन, आम अवाम एक होकर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हम बच्चों के अधिकार, संरक्षण, सुरक्षा, कल्याण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा से कोसों दूर रहेंगे। हम कहते तो हैं-बच्चे कल के भविष्य हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ ''भविष्य' के लिए करने की जरूरत है।

चलते चलते

सिक्स्टी नाइन

आज बाल दिबस ऐ, कोई बालकन जैसी बात करि सकै? मेरी तो सारी बात बच्चों की सी बात ही होती हैं, पर मुझसे भी ऊंचे उम्रदराज बच्चे धरती पर हैं। एक हैं उन्हत्तर वर्षीय डच नागरिक एमिल रैटलबैंड। पिछले हफ्ते वे अदालत पहुंच गए कि उनकी उम्र रिकॉर्ड्स में बीस साल कम कर दी जाए। वे अपनी आधिकारिक उम्र को लेकर सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी भावनात्मक उम्र का पता नहीं चलता। सिक्स्टी नाइन की जगह फौट्टी नाइन दर्ज कराना चाहते हैं। जब नाम बदले जा सकते है तो उम्र क्यों नहीं?-तौ वे उमर खरीद लैं काऊ ते!-अहा हा हा! पूछ रहे थे बच्चों जैसी बात, ये तो आपने बुजुगरे वाली बात कर दी। एक कहानी का प्लॉट दे दिया। प्लॉट को अभी डेवलप करता हूं। सुनिए, एक थे चचा

मेरी तो सारी बात बच्चों की सी बात ही होती हैं, पर मुझसे भी ऊंचे उम्रदराज बच्चे धरती पर हैं। एक हैं उन्हत्तर वर्षीय डच नागरिक एमिल रैटलबैंड। पिछले हफ्ते वे अदालत पहुंच गए कि उनकी उम्र रिकॉर्ड्स में बीस साल कम कर दी जाए। वे अपनी आधिकारिक उम्र को लेकर सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी भावनात्मक उम्र का पता नहीं चलता। सिक्स्टी नाइन की जगह फौट्टी नाइन दर्ज कराना चाहते हैं।

बगीची वाले। उम्र सत्तर साल। इस उम्र तक उन्होंने जितना काम किया, वे समझते थे कि कुछ खास नहीं किया, लेकिन लोगों का मानना ये था कि उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि जो किया उससे उनकी कमाई हुई। ऐसी बेशुमार कमाई हुई कि अगर उन्हीं की जीवन-शैली से जिया जाए तो सत्तर पुश्त तक भी वह पैसा खत्म न हो। उन्होंने सोचा कि सत्तर पुश्तों के बारे में क्यों सोचा जाए, इस पैसे से अपने लिए उम्र खरीदी जाए। तो चचा बगीची वाले निकल पड़े उम्र खरीदने।-अच्छा, फिर?-फिर उन्हें सामने से आता हुआ एक युवा साधु दिखाई दिया। उन्होंने कहा ''हे युवाचार्य महाराज! आप तो वैरागी हो चुके हैं, संसार से सन्यास ले चुके हैं, मोह-माया पर विजय पा चुके हैं, क्या आप मुझे अपनी उम्र दे सकते हैं? मेरे पास काफी पैसा है, मैं खरीद लूंगा।

चचा बगीची वाले उस युवा बाबाजी के बाबा के समान थे, पर वह युवाचार्य उनपर आग-बबूला होकर बोला, ''बच्चा! पैसा क्या दिखाता है, कमंडल टेढ़ा करूंगा तो जितनी सम्पत्ति तेरे पास है उसका दस गुना इसकी टोंटी से निकाल दूंगा। तू अगर अपनी उमर बेचता है तो बोल, साधू बना हूं मजे करने के लिए। चला है उम्र खरीदने! करता है बच्चों की सी बात!!

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न

जब हम ''भारत के लोग' अपना नया स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बाबा नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता का वह सवाल पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, जिसमें पहले वे पूछतेहैं : किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है? बाबा अपने सवाल को कौन त्रस्त, कौन पस्त और कौन मस्त तक भी ले जाते हैं, तो लगता है कि उन्हें आज की तारीख में हमारे सामने उपस्थित विकट हालात का पहले से इल्म था। इन हालात की विडम्बना देखिए : एक ओर तो अब हमारे नेता देश को समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित संकल्प को संविधान की पोथियों में भी चैन से नहीं रहने देना चाहते; और दूसरी ओर गैर-बराबरी का भस्मासुर न सिर्फहमारी बल्कि दुनिया भर की जनतांत्रिक शक्तियों के सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें धमकाने पर आमादा है कि लोकतंत्र की अपनी परिकल्पनाओं को लेकर किसी मुगालते में न रहें। अमीरी का जाया यह असुर उनके सारे के सारे मूल्यों को तहस-नहस करने का मंसूबा लिए उन्मत्त होकर आगे बढ़ा आ रहा है, और आरजू या मिनती कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। बड़े-बड़े परिवर्तनों के दावे करके आई नरेन्द्र मोदी सरकार को भी अपने चार सालों में इस अनर्थ नीति को बदलना गंवारा नहीं है। भले ही यह नीति कम से कम इस अर्थ में तो भारत के संविधान की घोर विरोधी है कि यह किसी भी स्तर पर उसके समता के मूल्य की प्रतिष्ठा नहीं करती और उसके संकल्पों के उलट आर्थिक ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के भी अंधाधुंध संकेंदण्र पर जोर देती है। यह सरकार इस सीधे सवाल का सामना भी नहीं करती कि किसी एक व्यक्ति के अमीर बनाने के लिए कितनी बड़ी जनसंख्या को गरीबी के हवाले करना पड़ता है, और क्यों हमें ''हृदयहीन' पूंजी को ब्रह्म और ''श्रम के शोषक' मुनाफे को मोक्ष मानकर ''सहृदय' मनुष्य को संसाधन की तरह संचालित करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए अनंतकाल तक अपनी सारी लोकतांत्रिक-सामाजिक नैतिकताओं, गुणों और मूल्यों की बलि देते रहना चाहिए? एक ओर इन सवालों के जवाब नहीं आ रहे और दूसरी ओर इन्हें पूछने वाले हकलाने लग गए हैं, तो साफहै कि हमारे लोकतंत्र में जनतांत्रिक विचारों की कमी खतरनाक स्तर तक जा पहुंची है।

यह कमी ऐसे वक्त में कोढ़ में खाज से कम नहीं है कि गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाने वाली आर्थिक नीति के करिश्मे अब किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। वे सारे लाभों को अमीर देशों के लिए सुरक्षित कर उन्हें और अमीर जबकि गरीब देशों को और गरीब बना रही हैं। एक प्रतिशत लोगों की अमीरी की यह उड़ान हमें कितनी महंगी पड़ने वाली है, जानना हो तो बताइए कि गरीबों के लिए इस गैरबराबरी से उबरने की कल्पना भी दुष्कर हो जाएगी तो वे क्या करेंगे? यही कारण है कि गत एक वर्ष में कांग्रेस मोदी के खिलाफ अनेक मुद्दे जोर-शोर से लेकर उठी लेकिन किसी भी मुद्दे को लंबे समय तक टिका नहीं सकी। हाल में सीबीआई की आंतरिक अस्थिरता की स्थिति को भी राफेल मामले से जोड़ा जाना राहुल और कांग्रेस द्वारा की जा रहीं गलतियों की कड़ी में ताजा नजीर है। कांग्रेस के सामने संकट यह नहीं है कि वह मोदी के खिलाफ मुद्दे खोज पा रही है या नहीं! संकट यह है कि वह मोदी के खिलाफ जनता के बीच उसके द्वारा उठाया गया कोई मुद्दा टिका नहीं।

सत्संग

अस्तित्वों का निर्माण

आपकी भावनाओं की, आपके विचारों की जो भी प्रकृति हो, पहले इन पर ध्यान देना सीखिए। देखिए जब आपको किसी चीज पर ध्यान देना होता है, तो आपको दो अस्तित्वों का निर्माण करना पड़ता है। आपकी भावनाएं केवल तभी बंधन बनती हैं, जब आपके और आपकी भावनाओं के बीच कोई दूरी नहीं होती। वहां आप खुद ही भावना बन जाते हैं। सारी समस्याओं की जड़ यही है। अगर आप ध्यान देना सीख लेंगे तो उनसे दूरी बनाने लगेंगे। अगर आप और आपकी भावनाओं के बीच दूरी हो, आप और आपके विचारों के बीच दूरी हो, आप और आपके शरीर के बीच दूरी हो, तो फिर ये सारी चीजें कोई समस्या नहीं रह जातीं। आपके पास एक शरीर है, यह कोई समस्या नहीं है, यह एक शानदार साधन है। आप सोचने के काबिल हैं, यह कोई समस्या नहीं है। जीवन को इतना विकास करने में लाखों वर्ष लगे कि वह सोचने के काबिल बन सके। तो विचार कोई समस्या नहीं है। बल्कि यह एक महान वरदान है कि हम सोच सकते हैं। आपके विचार क्रेजी हो गए हैं-नहीं आप क्रेजी हो गए हैं, इसलिए विचार एक समस्या लगता है। आपकी भावनाएं कोई समस्या नहीं है, बिना भावनाओं के आप एक सूखी लकड़ी की तरह होंगे। ये भावनाएं ही हैं, जो आपके जीवन को मधुर और खूबसूरत बनाती हैं। ये भावनाएं ही हैं, जो आपके जीवन में प्रवाह लाती हैं। लेकिन यही भावनाएं तब एक समस्या बन जाती हैं, जब ये आपके नियंतण्र से बाहर जाकर पागलपन का रूप ले लेती हैं। अगर आप भावनाओं पर ध्यान देते हैं, उनके प्रति जागरूक होते हैं, तो आप जैसे-जैसे जागरूक होते जाएंगे, वैसे-वैसे आपके और इनके बीच दूरी बढ़ती जाएगी। आप अपने विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं, आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन आप भावना नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तब आप किस तरह की भावना पैदा करेंगे? सबसे मधुर भावनाएं। अगर आप सजगता से अपने विचारों का इस्तेमाल करें तो आप किस तरह के विचार पैदा करेंगे? आप ऐसे विचारों को पैदा करेंगे, जो आपके हित में हों या आपके खिलाफ हों? निश्चित रूप से अपने हित से जुड़े विचारों को पैदा करेंगे।

फोटोग्राफी...

कोच्चि में मंगलवार को इंडियन ओशन नैवल सिम्पोजियम के दौरान केक काटते नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा और ईरान के नौसेना कमांडर होसैन खनजादी।

बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 2 तो निफ्टी 6 अंक गिरा

मुंबई। कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बुधवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई का 31 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 2.50 अंक (0.01 फीसदी) की गिरावट के साथ 35,141.99 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी मात्र 6.20 अंकों की गिरावट के साथ 10,576.30 पर बंद हुआ। मंगलवार को सेंसेक्स 331.50 अंकों (0.95 फीसदी) की उछाल के साथ 35,144.49 पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 100.30 अंकों (0.96 फीसदी) की तेजी के साथ 10,582.50 पर बंद हुआ था।

दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 35,351.88 का उच्चतम स्तर, तो 34,986.86 का निम्नतम स्तर छुआ। वहीं निफ्टी ने 10,651.60 का उच्चतम स्तर, तो 10,532.70 का निम्नतम स्तर छुआ। बीएसई पर 14 शेयर हरे निशान में, 17 शेयर लाल निशान में बंद हुए। एनएसई पर 23 शेयर हरे निशान में और 27 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

बीएसई पर मारुति के शेयर मे 3.16 फीसदी, एशियन पेंट के शेयर में 2.73 फीसदी, ओएनजीसी के शेयर में 2.72 फीसदी, इंडसइंड बैंक के शेयर में 1.95 फीसदी और हिंदुस्तान यूनीलीवर के शेयर में 1.91 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वहीं, सन फार्मा के शेयर में 7.36 फीसदी, कोटक बैंक के शेयर में 3.04 फीसदी, टीसीएस के शेयर में 2.85 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में 2.62 फीसदी और इन्फोसिस के शेयर में 1.84 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

उधर, एनएसई पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर में 4.04 फीसदी, बीपीसीएल के शेयर में 3.60 फीसदी, यूपीएल के शेयर में 3.05 फीसदी, मारुति के शेयर में 2.79 फीसदी और इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन के शेयर में 2.69 फीसदी की तेजी देखी गई। जबकि, सन फार्मा के शेयर में 7.29 फीसदी, टेक महिंद्रा के शेयर में 3.58 फीसदी, गेल के शेयर में 3.52 फीसदी, कोटक बैंक के शेयर में 3.51 फीसदी और एचसीएल टेक के शेयर में 3.50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

टाटा ट्रस्ट्स ने सोशलअल्फा के साथ मिलकर उद्यमियों के लिये शुरू किया फेलोशिप

नयी दिल्ली। टाटा ट्रस्ट्स और सोशल अल्फा ने नवोन्मेषी विचारों से प्रभावी उपक्रम बनाने की सोच रहे उद्यमियों के लिए बुधवार को 12 महीने के एक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरूआत की। टाटा ट्रस्ट्स ने एक बयान में कहा कि 'सोशल अल्फा एंटरप्रेन्योर्स फॉर इम्पैक्ट (ई4आई)' कार्यक्रम के तहत जल, सफाई, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में आठ उद्यमियों के पहले समूह को चुना जाएगा। बयान में बताया गया कि इस फेलोशिप के लिये छह जनवरी 2019 तक सोशलअल्फाचैलेंज डॉट ओआरजी पर आवेदन किया जा सकता है। चयनिक उद्यमियों को 12 महीने तक प्रति माह 60 हजार रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा। सोसल अल्फा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आज किसानों को अपने खेत की मिट्टी की ऊर्वरा शक्ति की जांच कराने के लिए मीलों दूर जाना होता है। पर कल को यही उद्यमी जांच के उसी विचार को लेकर काम शुरू कर सकते हैं। वे खुद चल का किसान के दरवाजे पर यह सुविधा दे सकते हैं। सोसल अल्फा की स्थापना 2016 में की गयी थी। यह टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त पहल है।

रॉयल एनफील्ड के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

चेन्नई। मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी के कर्मचारी विभिन्न मांगों मसलन वेतन संशोधन और बोनस आदि को लेकर 24 सितंबर से हड़ताल पर थे। मंगलवार को कर्मचारी काम पर लौट आए। रॉयल एनफील्ड ने कहा कि उसके तीनों संयंत्रों...ओरागदम, तिरुवोत्तियुर और वल्लम वदागल में पूर्ण क्षमता से परिचालन शुरू हो गया है।

वर्किंग पीपी ट्रेड यूनियन काउंसिल और रॉयल एनफील्ड एम्पलाइज यूनियन के उपाध्यक्ष आर संपत ने पीटीआई भाषा से कहा कि कंपनी के 6,000 में से 4,000 कर्मचारी हड़ताल पर थे। कर्मचारी प्रबंधन द्वारा उनके मोबाइल फोन सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने का भी विरोध कर रहे थे। रॉयल एनफील्ड ने बयान में कहा, ''कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखने को प्रतिबद्ध है। हम अनुशासन के उच्चस्तर, टीम वर्क और एक दूसरे के लिए सम्मान के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं।''

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर 'सहमति' का प्रयास कर रहे हैं रिजर्व बैंक, सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ओर से प्रसास है कि खास कर कमजोर बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंकुशों में ढ़ील देने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कर्ज के नियमों को सरल बनाने के बारे में सहमति के सामधान तय किए जा सकें.

सूत्रों ने कहा कि बोर्ड की इस बैठक में न सही पीसीए रूपरेखा पर कोई सहमति अगले कुछ सप्ताह में जरूर बन जाएगी. वित्त मंत्रालय लगातार इसके लिए दबाव बना रहा है. यदि पीसीए नियमों को उदार कर दिया जाता है तो कई बैंक इस वित्त वर्ष के अंत तक पीसीए के अंकुश से बाहर आ जाएंगे.

सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में से 11 पर आरबीआई ने पीसीए का शिकंजा कस रखा है जिसके तहत उन्हें कर्ज स्वीकृत करने पर कई तरह की रोक लगी हुई है. ये बैंक हैं- इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र.

पीसीए व्यवस्था तब लागू होती है जबकि वाणिज्य बैंक आरबीआई द्वारा सुरक्षित बैंकिंग कारोबार के बारे में तय तीन प्रमुख कसौटियों में से किसी एक भर भी विफल हो जाते हैं. ये तीन नियामकीय व्यवस्थाएं हैं- पूंजी से जोखिम भारांश संपत्ति अनुपात, शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियां, संपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए).

सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के नियमों को उदार करने पर सहमत हो सकता है. इसमें सख्त रेटिंग मानदंड भी शामिल है जिससे इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ सके. इसके अलावा ऐसी उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एमएसएमई तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विशेष व्यवस्था पर विचार कर सकता है. ये क्षेत्र नकदी संकट से जूझ रहे हैं.

सरकार का मानना है कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है. यह क्षेत्र नोटबंदी तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद काफी प्रभावित हुआ है और इसे समर्थन की जरूरत है. हालांकि, केंद्रीय एमएसएमई तथा एनबीएफसी क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था के पक्ष में नहीं है क्योंकि वह इन्हें संवेदनशील क्षेत्र मानता है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले सप्ताह कहा था कि एनपीए को कम से कम करने की जरूरत है ताकि बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को कायम रखा जा सके जिससे यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद दे सके.

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर 'सहमति' का प्रयास कर रहे हैं रिजर्व बैंक, सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक से पहले सरकार और केंद्रीय बैंक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों ओर से प्रसास है कि खास कर कमजोर बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंकुशों में ढ़ील देने और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए कर्ज के नियमों को सरल बनाने के बारे में सहमति के सामधान तय किए जा सकें। सूत्रों ने कहा कि बोर्ड की इस बैठक में न सही पीसीए रूपरेखा पर कोई सहमति अगले कुछ सप्ताह में जरूर बन जाएगी।

वित्त मंत्रालय लगातार इसके लिए दबाव बना रहा है। यदि पीसीए नियमों को उदार कर दिया जाता है तो कई बैंक इस वित्त वर्ष के अंत तक पीसीए के अंकुश से बाहर आ जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में से 11 पर आरबीआई ने पीसीए का शिकंजा कस रखा है जिसके तहत उन्हें कर्ज स्वीकृत करने पर कई तरह की रोक लगी हुई है। ये बैंक हैं...इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स, देना बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र। पीसीए व्यवस्था तब लागू होती है जबकि वाणिज्य बैंक आरबीआई द्वारा सुरक्षित बैंकिंग कारोबार के बारे में तय तीन प्रमुख कसौटियों में से किसी एक भर भी विफल हो जाते हैं।

ये तीन नियामकीय व्यवस्थाएं हैं..पूंजी से जोखिम भारांश संपत्ति अनुपात, शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियां, संपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए)। सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के नियमों को उदार करने पर सहमत हो सकता है। इसमें सख्त रेटिंग मानदंड भी शामिल है जिससे इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ सके। इसके अलावा ऐसी उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एमएसएमई तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विशेष व्यवस्था पर विचार कर सकता है। ये क्षेत्र नकदी संकट से जूझ रहे हैं। सरकार का मानना है कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र नोटबंदी तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद काफी प्रभावित हुआ है और इसे समर्थन की जरूरत है। हालांकि, केंद्रीय एमएसएमई तथा एनबीएफसी क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था के पक्ष में नहीं है क्योंकि वह इन्हें संवेदनशील क्षेत्र मानता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले सप्ताह कहा था कि एनपीए को कम से कम करने की जरूरत है ताकि बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को कायम रखा जा सके जिससे यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद दे सके।

ट्विटर के मुख्य कार्यकारी जैक डोरसे ने मोदी से मुलाकात की

नयी दिल्ली। ट्विटर के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर वैश्विक संवाद के महत्व पर बातचीत की। मुलाकात के बाद डोरसे ने मोदी के साथ बैठक की तस्वीरें साझा कीं और लिखा, '' आज हमारे साथ समय गुजारने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपके साथ वैश्विक संवाद के महत्व के बारे में चर्चा करके मैं प्रसन्न हूं। ट्विटर के लिए आपके सुझावों का धन्यवाद।'' इसके जवाब में मोदी ने कहा, '' आपसे मिलकर खुशी हुई जैक। ट्विटर का नेतृत्व करने के लिए आपका जुनून देखकर खुश हूं। मैं इस माध्यम का उपयोग करके खुश हूं जहां मैंने कई अच्छे दोस्त बनाए हैं और रोज लोगों की रचनात्मकता को देखता हूं।''

थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 5.28/ हुई, पिछले 4 महीने का उच्चतम स्तर

नई दिल्ली (एजेंसी)।

खाद्य पदार्थों के दाम नरम पड़ने के बाद भी पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में बढ़कर चार माह के उच्च स्तर 5.28 प्रतिशत पर पहुंच गयी। थोक मुद्रास्फीति पिछले महीने यानी सितंबर में 5.13 प्रतिशत तथा पिछले साल अक्टूबर में 3.68 प्रतिशत थी। सरकार द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों में नरमी देखी गयी। इनमें सितंबर के 0.21 प्रतिशत की तुलना में अक्टूबर में 1.49 प्रतिशत अपस्फीति देखी गयी।

इस दौरान सब्जियों के भी भाव गिरे। सब्जियों के भाव आलोच्य माह के दौरान 18.65 प्रतिशत कम हुए। सितंबर में इनमें 3.83 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। ईंधन एवं विद्युत बास्केट में महंगाई सितंबर के 16.65 प्रतिशत की तुलना में अक्टूबर में 18.44 प्रतिशत रही। पेट्रोल और डीजल के भाव इस दौरान क्रमशः 19.85 प्रतिशत और 23.91 प्रतिशत बढ़े। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के दाम भी अक्टूबर में 31.39 प्रतिशत बढ़े।

खाद्य पदार्थों में अक्टूबर महीने में आलू के दाम 93.65 प्रतिशत बढ़े। हालांकि प्याज 31.69 प्रतिशत और दाल 13.92 प्रतिशत सस्ते हुए। अक्टूबर की 5.28 प्रतिशत की थोक महंगाई चार महीनों का उच्चतम स्तर है। इससे पहले जून में यह दर 5.68 प्रतिशत रही थी।अक्टूबर महीने की थोक महंगाई की चाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई से उलट रही है। खुदरा महंगाई कम होकर एक साल के निचले स्तर 3.31 प्रतिशत पर आ गयी है। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तय करते हुए मुख्यतः खुदरा महंगाई को ही ध्यान में रखता है।

पैसा जुटाने को कई पक्षों से बातचीत कर रही जेट एयरवेज

मुंबई। नकदी संकट जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने मंगलवार को कहा कि पैसा जुटाने के लिए वह 'इच्छुक भागीदारों' के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही है। साथ ही उसकी योजना अपने लॉयल्टी कार्यक्रम जेट प्रिवलेज में थोड़ी हिस्सेदारी बेचने की भी है। गौरतलब है कि जेट एयरवेज अपने नकदी संकट से निपटने के लिए निवेशकों की बाट जोह रही है। संकट के चलते उसके करीब 16,000 कर्मचारियों का वेतन देने में देरी हुई है। कंपनी के उप मुख्य कार्यकारी और मुख्य वित्त अधिकारी अमित अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि हम नकदी जुटाने की विभिन्न स्तरों पर पहल कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज आज, व्यापार सुस्त रहने के संकेत: सूत्र

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

सूत्रों के मुताबिक इस साल अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से 6-7 करोड़ रुपए के व्यापार की उम्मीद है. जो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है. पिछले साल 25 करोड़ का व्यापार हुआ था और उससे पिछले साल 50 करोड़ के आस-पास. इस साल क्योंकि मेला प्रगति मैदान के 25 फीसदी हिस्से में लग रहा है इसलिए व्यापार भी बहुत कम होगा ऐसी आशंका जताई गई है.

आईटीपीओ (इंडिया ट्रेड प्रमोडॉशन आर्गनाइजेशन) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले दो साल से जगह की कमी और बाजार की हिस्सेदारी कम होने की वजह से व्यापार भी मंदा हो रहा है. पिछले साल 25 करोड़ का हुआ था और इस साल तो और कम 6-7 करोड़ का हो सकता है. बस एक नियम के तहत ये मेला आयोजित हो रहा है.

इस साल मल्टीनेशनल कंपनी और राज्यों की हिस्सेदारी आधी है. 800 स्टाल प्रदर्शनी के लिए है और 25 फीसदी एरिया में मेला आयोजित हुआ है. ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस बार थीम भी छोटे और ग्रामीण उद्योग को रखा गया है. लेकिन ज्यादा फुटफॉल की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं. हमने 25 हजार प्रति दिन का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है 20 हजार तक लोग आएंगे.

गौरतलब है कि आज अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज हो गया. 14 -27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में हाथों से बनी चीजों की प्रदर्शनी है. राजस्थान, ओड़िशा, हिमाचल, पंजाब , बंगाल , दिलली, कश्मीर और भी कई राज्यों से कारीगर अपनी प्रदर्शनी लेकर यहां आए हैं. इस बार भी बुक माई शो और मेट्रो स्टेशन पर टिकट मिल रही है और आम लोग 17 से मेले में आ सकते हैं. मेट्रो गेट नंबर 8-10.

व्यापारी ने साड़ी पर जॉबवर्क करवाने के बाद 51 हजार नहीं चुकाकर दी जान से मारने की धमकी

सूरत। शहर के कपड़ा बाजार रिंग रोड पर स्थित अनुपम मार्केट में व्यापारी ने समय पर पेमेन्ट चुकाने का वादा कर साड़ी पर लेस जॉब करवाने के बाद मजदूरी के 51 हजार रूपए नहीं चुकाये और व्यापारी ने वसूली करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवायी गई है।

सलाबतपुरा पुलिस सूत्रों के अनुसार गोडादरा मानसरोवर सोसायटी निवासी विवेक बाबु सावय साड़ी पर लेस लगाने का जॉबवर्क करते है। उनके पास से जुलाई माह में रिंग रोड अनुपम मार्केट में सुनिधि क्रिएशन का संचालक प्रकाश ने समय पर पेमेन्ट चुकाने का वादा कर साड़ियों पर जॉबवर्क करवाया था। जिसकी 51762 रूपए मजदूरी हुई थी। समय मर्यादा में पेमेन्ट नहीं चुकाने पर विवेक ने बारंबार वसूली की। फिर भी पेमेन्ट नहीं चुकाया। इस दौरान ने प्रकाश ने पेमेन्ट की वसूली करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।

महिला को रास्ते पर अनाज खरीदना पड़ा महंगा

सूरत। शहर महीधरपुरा के गलेमंडी चौराहे से दिल्लीगेट जा रही महिला को बीच रास्ते में रिक्शा रूकवाकर अनाज खरीदना लाखों में पड़ा। इस बीच रिक्शा चालक गहने रखी थैली लेकर फरार हो गया। महीधरपुरा पुलिस सूत्रों के अनुसार भरूच के प्रितम सोसासटी निवासी चंद्रिकाबेन हरिशभाई परीख गत रोज शाम को गलेमंडी में स्थित सी. ज्वेलर्स वाले को दिए 4.26 लाख रूपए के गहने लेने के लिए आई थी और गहने खरीदकर थैले में रखकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए गलेमंडी से दिल्लीगेट जाने के लिए रिक्शा किराये से की थी। इस दौरान दिल्लीगेट से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे रास्ते में एक जगह दाल खरीदने के लिए गाड़ी रूकवाई। चालक ने ट्रैफिक का बहाना बनाकर आगे रिक्शा ले जाने की बात कहकर 4.26 लाख के गहने रखे थैली लेकर फरार हो गया। महिला को रास्ते में अनाज खरीदना लाखों में पड़ा। घटना के संदर्भ में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।

बाइकर्स ने महिला का पर्स छीना

सूरत। शहर में स्नेचरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आये दिन स्नेचर वारदातों को अंजाम दे रहे है। इस बीच वेसु इलाके में गत रोज शाम को गुजर रही एक महिला के गले से पर्स छीनकर बाइकर्स फरार हो गए। पर्स में नगद 6 हजार और 35 हजार की कीमत की मोबाइल रखा था।

एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

सूरत। शहर के लिंबायत इलाके स्थित गोडादरा मंगलपांडे हॉल निकट एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ कर रूपए चोरी करने वाले दो जनों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से हथौड़ा, कुल्हाड़ी समेत अन्य हथियार जब्त किए।

लिंबायत पुलिस सूत्रों के अनुसार गत रात को ढाई बजे गोडादरा मंगलपांडे हॉल के पास एसबीआई बैंक में एटीएम की तोड़फोड़ कर एटीएम से पैसे चोरी करने पर नगर सोसायटी, गोडादरा निवासी प्रकाश भुदर लवजी धामेचा और आसपास मंदिर के पास, लिंबायत निवासी सागर हीरा राठौड़ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसकी कुल्हाड़ी, हथौड़ा समेत अन्य हथियार बरामद किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस कमिशनर ने सीट की रचना की

ठग के २६० करोड़ रुपये के घोटाले में सीट की रचना

सेक्टर-१ के संयुक्त पुलिस कमिशनर की अध्यक्षता में ३ आईपीएस अधिकारियों को सीट में शामिल किया गया

अहमदाबाद । थलतेज में स्थित प्रेसिडेन्ट प्लाजा में वर्ल्ड कलेक्टरेक्स सोल्युशन कंपनी तथा आर्चर केयर डीजी एलएलपी कंपनी के मालिक विनय शाह और इसकी पत्नी भार्गवी शाह एक लाख ग्राहकों का २५६ करोड़ रुपये का घोटाला करके फरार हो जाने के मामले में और दो शिकायत निकोल पुलिस स्टेशन और वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई है। दूसरी तरफ, पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में लेकर अहमदाबाद शहर पुलिस कमिशनर द्वारा स्पेश्यल इन्वेस्टीगेशन टीम (सीट) की रचना की गई है। जिसमें सेक्टर-१ के संयुक्त पुलिस कमिशनर की अध्यक्षता में तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है, इस मामले में जांच की जाएगी । दूसरी तरफ, राज्य के गृह विभाग ने भी घोटाले की गंभीरता को ध्यान में लेकर राज्य के जिला पुलिस प्रमुखों को यह मल्टी लेवल मार्केटिंग के मामले में जांच करना और अवैध रूप से चल रही ऐसी कंपनियों की जानकारियों को एकत्र करने की सूचना जारी की गई है।

इस घोटाले में विनय शाह और भार्गवी सहित अब ग्राहकों द्वारा उनके एजेन्टों के नाम भी सामने आये हैं । निकोल और वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन विनय और इसके दो एजेन्ट के विरूद्ध में शिकायत हुई है । करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले विनय इसकी पत्नी सहित एजेन्ट दानसिंहवाला अपने परिवार के साथ फरार हो गया है तब एक महिला एजेन्ट प्रगति व्यास और मुकेश सोनी भी फरार हो गया है । उल्लेखनीय है कि, करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर बापूनगर में रहते अमित व्यास नाम के व्यक्ति ने दो महीने पहले क्राइम ब्रांच के प्रमुख जेके. भट्ट से शिकायत की थी हालांकि अभी क्राइम ब्रांच ने यह शिकायत पर कोई कामकाज नहीं करने पर कई प्रश्न खड़े हो गये हैं । पालडी के यूनियन फ्लेट में रहते विनय शाह और भार्गवी शाह ने वर्ल्ड कलेक्टरेक्स सोल्युशन कंपनी तथा आर्चर केयर डीजी एलएलपी कंपनी खोली थी। वह कंपनी की आड़ में पांच हजार से लेकर २५ हजार रुपये तक की रकम डीपोजिट के तहत लेते थे । वह ग्राहकों को ऑनलाइन वेबसाइट पर विज्ञापनों को देखने का बताकर इसके बदले में १८ फीसदी मुआवजा हर महीने देने का कहता था । इस प्रकार से ठग कपल ने एक लाख ग्राहक बनाकर २५६ करोड़ रुपये वसूल कर लिया था।

पुलिस ने रिवरफ्रन्ट पर हेल्मेट का अभियान चलाया

हेल्मेट नहीं पहना तो अब १०० रुपये का जुर्माना होगा

सुप्रीम के आदेश अनुसार बनाई गई रोड सेफ्टी कमिटी में ३४ फीसदी हेल्मेट नहीं पहनते होने की बात सामने आई

अहमदाबाद । शहर में यदि अब आप टू व्हीलर पर निकले हो और हेल्मेट नहीं पहना हो तो १०० रुपये का जुर्माना निश्चित है । सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार काम करती रोड सेफ्टी कमिटी के सर्वे में ३४ फीसदी शहरीजन हेल्मेट पहनते होने की बात सामने आने पर पुलिस सक्रिय हो गई है । पुलिस द्वारा किसी भी क्षेत्र में एक पोइन्ट बनाकर ४० पुलिसकर्मी हेल्मेट पहने बिना जाते वाहनचालकों के पास से जुर्माना वसूल करेगी । शहर ट्राफिक पुलिस ने रिवरफ्रन्ट सहित के क्षेत्रों में हेल्मेट का अभियान चलाकर दोषी वाहनचालकों के पास से जुर्माना वसूल किया गया । शहर ट्राफिक पुलिस द्वारा आगामी दिनों में भी यह अभियान को जारी रखने की संभावना है । दूसरी तरफ, हेल्मेट को लेकर पुलिस की फिर एक बार शुरू की गई सख्ती को लेकर नागरिकों में नाराजगी फैल गई है। पिछले दो दिन से अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्र में शहर ट्राफिक पुलिस द्वारा हेल्मेट बिना के वाहनचालकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है । बुधवार को सुबह में साबरमती रिवरफ्रन्ट पर नो हेल्मेट नो गो जोन करके हेल्मेट पहने बिना वाहनचालकों से जुर्माना वसूल किया गया । गत दिन भी साबरमती रिवरफ्रन्ट वल्लभसदन के पास भी ड्राइव आयोजित करके २४०० से ज्यादा शहरीजनों से से जुर्माना वसूल किया गया । आगामी दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्र में पुलिस ने हेल्मेट बिना के वाहनचालकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी। ट्राफ्रिक डीसीपी (वेस्ट जोन) डॉ. संजय खरात ने बताया है कि, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार काम करती रोड सेफ्टी कमिटी के सर्वे में ३४ फीसदी शहरीजन हेल्मेट पहनते होने की बात सामने आने पर अब अलग-अलग जगहों पर ड्राइव शुरू की गई है । एन्फोर्समेन्ट और अवेरनेस द्वारा लोगों को हेल्मेट पहनने के लिए जागृत किया जाएगा । ३४ फीसदी से यह रेशियो ६० से ७० फीसदी तक पहुंचे ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में आधुनिक पुस्तक प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

जमीन विकास निगम की ऑफिस बंद करने का निर्णय

अहमदाबाद । राज्य के सबसे बड़ा घोटाला कॉर्पोरेशन के तौर पर सामने आये जमीन विकास निगम को आखिर में सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार ने जमीन विकास निगम को बंद करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, फिलहाल जहां तक कामकाजक खत्म नहीं होगा वहां तक निगम चालू रहेगा । दूसरी तरफ, निगम के स्टाफ कर्मचारियों और वाहनों को भी सरकार के अन्य विभागों में जरूरत के अनुसार आवंटन कराया जाएगा । यह घोटाले में निगम के सभी टोप के अधिकारी शामिल होने का सामने आया है। अब राज्य सरकार ने जमीन विकास निगम को बंद करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार जमीन विकास निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया है। निगम के ४०० कर्मचारी अन्य सरकारी विभागों में या बोर्ड कॉर्पोरेशन में शामिल किया जाएगा । इसके अलावा निगम के तहत जो कई योजना है यह कई योजना को सीधे तरीके से सिंचाई और कृषि विभाग के तहत चालू रखा जाएगा । जबकि जमीन विकास निगम की संपत्तियों को सरकार हस्तक लेकर अन्य सरकारी काम के लिए आवंटन कराया जाएगा। सरकार के जमीन विकास निगम को बंद करने की बात ऐसे तो सरकार और प्रशासन के लिए शर्मजनक कहा जा सकता है क्योंकि घोटाला को रोकने की बातें करने वाले भाज पा के शासन में यदि इसके एक निगम में घोटाला होता हो तो और यह निगम बंद करना अनिवार्य हो गया इस तरह सरकार के लिए यह निर्णय एक झटका के समान है।

जलाराम जयंति को भव्य तरीके से मनाया गया। पालडी में जलाराम मंदिर में अन्नकूट दर्शन का आयोजन किया गया।'

शहर में महिलाओं के गले में से चेन स्नेचिंग की घटना बढ़ी

अहमदाबाद । शहर में चेन स्नेचरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है । सरकार के चेन स्नेचिंग को लेकर सख्त कानून और पुलिस की सुरक्षा के दावे के बीच शहर में वेजलपुर, शाहीबाग सहित के क्षेत्रों में चेन स्नेचिंग की गंभीर घटनाएं सामने आने पर महिलाओं-बुज ुर्ग लोगों में दहशत फैल गई। वेज लपुर और शाहीबाग क्षेत्र में चेन स्नेचरों ने महिलाओं के गले में से सोने की चेन खींचकर फरार हो गये । जीवराजपार्क क्षेत्र में स्थित सत्यनारायण सोसाइटी में रहते ज ल्पाबहन अनीकेतभाई गोहिल ने वेज लपुर पुलिस स्टेशन में चेन स्नेचरों के विरूद्ध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, जल्पाबहन वेजलपुर रोड पर स्थित मानवमंदिर पान पार्लर की तरफ से चलते हुए जा रहे थे तब बाइक पर आये दो शख्स उनके गले में से १५ हजार रुपये की सोने की चेन खींचकर फरार हो गये। पुलिस ने यह मामले में अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शाहीबाग क्षेत्र में स्थित नारायण कॉम्प्लेकस में रहती दक्षाबहन हसमुखभाई राठोड ने भी शाहीबाग पुलिस स्टेशन में चेन स्नेचरों के विरूद्ध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दक्षाबहन शाहीबाग रचना स्कूल के पास से जा रही थी तब बाइक पर आये दो शख्सों ने उनके गले में से २० हजार रुपये की चेन खींचकर ले गये। शाहीबाग पुलिस ने यह मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शहर में चेन स्नेचरों का आतंक चालू रहने से महिलाओं और बुजुर्ग लोगों की चिंता बढ़ गई है जैसे पुलिस निष्क्रिय बन गई हो ऐसा लग रहा है यह पूरे मामले में अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई करके समाज को सुरक्षा का अहसास कराना चाहिए ऐसी मांग नागरिकों की तरफ से की गई है।

यूनिवर्सिटी परिसर में रिनोवेशन का काम चल रहा है जिसके तहत कई पेड़ काटे गये हैं।

पेट्रोल पंप के कर्मचारी की तकरार में ग्राहक ने हत्या की

अहमदाबाद । शहर के असारवा में स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए आये ग्राहक ने पेट्रोल पंप के बुजुर्ग कर्मचारी के साथ हुई मामूली तकरार में नाराज होकर उसने पेट्रोल भरने की नोजल सिर में मारकर मौत के घाट उतार दिया इस वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई । इस घटना के मामले में शाहीबाग पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। असारवा क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर टू व्हील वाहन में पेट्रोल भरवाकर पंप के बुज ुर्ग कर्मचारी के साथ भैरव नाम के एक व्यक्ति ने विवाद शुरू किया। इसके बाद मारपीट की गई उसने पेट्रोल भरने की नोजल पंप कर्मचारी के सिर में वार कर दिया था। जिसकी वजह से वह नीचे गिर गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

दूसरी तरफ, गंभीर रूप से घायल हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारी का उपचार के दौरान उनका निधन होने पर पुलिस ने यह प्रकरण में शामिल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। हालांकि, इस घटना को लेकर पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों और पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई । दूसरी तरफ, सरसपुर में बीपिन परमार की पिटाई करके मौत के घाट उतार देने की घटना में शहरकोटडा पुलिस ने मुख्य सूत्रधार भैरव उर्फ भेरू कुमावत सहिच चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भैरव के अलावा रवि पांडे, विक्रम चौहान और दीपक उर्फ दीपो हीरागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भैरव, रवि और दीपक का क्रिमीनल इतिहास रहा है। जिसमें भैरव ओढव, रामोल, बापूनगर, नरोडा, नारायणपुरा, और सुरेन्द्रनगर में विभिन्न अपराध में पुलिस चोपडे में दर्ज हो चुका है। रामोल और ओढव में तडीपार है। जबकि रवि पांडे के विरूद्ध रामोल पुलिस स्टेशन में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विक्रम चौहान रामोल में प्रोहिबिशन और मारपीट के अपराध में गिरफ्तार हो चुका है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)